(c) to (e). Electricity consumption in Vithalbhai Patel House is being charged at the rate of 29 paise per unit against 27 paise per unit in other localities like South Avenue, North Avenue and Meena Bagh. The case for reducing the rate of electric consumption to 27 paise per unit from 29 paise per unit now charged is under consideration of New Delhi Municipal Committee, who have since submitted the proposal for approval to the Lt. Governor. Recovery of water charges is made at the same rates from occupants of V.P. House as are recovered from occupants of other localities by the New Delhi Municipal Committee direct.

Utilisation of Waters of Rivers Ravi and Beas in Punjab, Haryana and Rajasthan

7846. SHRI S. S. SOMANI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) what are the details of the released water from Pakistan and utilized under the Indus Water Treaty of 1960 of the rivers Ravi and Beas, in Punjab, Haryana and Rajasthan separately during the last three years, and

(b) what is the quantity of stored water made available for irrigation during the last two years after the construction of the Talwara Dam on River Beas to Rajasthan, Haryana and Punjab separately?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). At the end of the transition period on 31st March, 1970 provided in the Indus Waters Treaty, 1960, the entire flow of the Ravi and the Beas became available for un-restricted use by India. The total average annual flow of these two rivers is about 19 MAF, of which India was utilizing about 9.8 MAF on an average at the end of the said transition period. The approximate figure of utilisation of the waters of these two rivers in MAF by the States of Rajasthan, Punjab and Haryana during the last three years are given below:—

Year (April-March)	Rajasthan	Punjab	Harayana*
1974-75	5·483	5 577	0·980
1975-76	6·108	5 487	0·977
1976-77	6 220	5·136	1·028

*Share of the water conserved in Bhakra and used therefrom in lieu of use of Ravi-Beas waters in Bhakara areas ex-Sirhind Feeder

The utilisation of the waters of Ravi and Beas is integrated and separate figures river-wise as well as for stored and free flow supply are not available.

घाटे में चल रही बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

7847. श्री जगन्नाथ जावलकार : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि प्रत्येक राज्य में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं घाटे में चल रही हैं ,

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितना घाटा हुआ और वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान प्रत्येक राज्य में अनुमानत: कितना घाटा होने की सम्भावना है ;

(ग) विभिन्न राज्यों में घाटे के क्या कारण हैं, और

(घ) क्या घाटे से बचने और उसमें कमी करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) बहुप्रयोजनी नदी घाटी परियोजनाओं पर 1976–77 में हुई राज्यवार हानि के सम्बन्ध में उपलब्ध अद्यतन जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों को सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय बोझ को उठाने के लिए पर्याप्त राशि से कम राजस्व प्राप्त होने के कारण निम्नलिखित हैं :—

1. राज्य सरकार द्वारा ली जा रही कम जल शुल्क दरें।
2. विभिन्न राज्यों द्वारा जहां खुशहाली कर अधिनियम लागू हो गया है, खुशहाली कर की वसूली न होना।
3. विभिन्न कारणों से सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने में लम्बा समय लग जाना।
4. सृजित सिंचाई क्षमता के समुचित दोहन में विलम्ब।
5. निर्माण और अनुरक्षण की लागत में भारी वृद्धि।

(घ) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई के लिए जल शुल्क दरें राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ये जल शुल्क दरें एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है और कुछ मामलों में तो एक ही राज्य में एक परियोजना से दूसरी परियोजना में भिन्न-भिन्न हैं। इस समय जो जल शुल्क दरें ली जा रही हैं वे कुल कार्यचालन खर्चों और ब्याज की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जल शुल्क दरों में वृद्धि करने और उन्हें युक्ति संगत बनाने के प्रश्न पर कई सम्मेलनों और बैठकों में विचार किया गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दरों का युक्तिसंगत ढांचा बनाने के लिए अन्तर्विभागीय जल शुल्क दर पुनरीक्षण बोर्ड स्थापित करें।

विवरण

वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक सिंचाई वर्क्स पर तथा बहुप्रयोजनी नदी घाटी परियोजनाओं पर 1976–77 में हुई हानि का राज्य वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1976–77 में सिंचाई वर्क्स पर हुई हानि		
		वाणिज्यिक सिंचाई	गैर-वाणिज्यिक सिंचाई	जोड़
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	31.47	—	31.47
2.	असम	—	0.28	0.28
3.	बिहार	10 25	—	10.25
4.	गुजरात	22 01	—	22.01

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	14.33	0.46	14.79
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	0.90	0.42	1.32
8.	कर्नाटक	19.08	0.92	20.00
9.	केरल	3.30	—	3.30
10.	मध्य प्रदेश	15.98	—	15.98
11.	महाराष्ट्र	22.76	—	22.76
12.	मणिपुर	—	—	—
13.	मेघालय	—	—	—
14.	नागालैण्ड	—	—	—
15.	उड़ीसा	6.10	2.15	8.25
16.	पंजाब	7.55	—	7 55
17.	राजस्थान	15.49	2.98	18.47
18.	सिक्किम	—	—	उपलब्ध नही
19.	तमिलनाडु	8.83	1.78	10.61
20.	त्रिपुरा	—	0.22	0.22
21.	उत्तर प्रदेश	40.36	0.02*	40.34
22.	पश्चिम बंगाल	16.64	—	16.64
	जोड़ राज्य	235.05	9.19	244.24

* लाभ का द्योतक है ।

Nehru Soviet land award to Officer of National Centre for Blind

7848. SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER:

SHRI MANOHAR LAL:

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have granted permission for the acceptance of Nehru Soviet Land Award to an Officer of the National Centre for the Blind for translation and publication of the works of Russian authors in Braille;

(b) if so, the names of books translated by the author from Russian into Indian Languages;

(c) the names of Indian Languages into which they were published;

(d) the names of Indian publishers in Braille; and

(e) whether the cost of publication was borne by Government?